दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 18 मार्च 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 168

महत्वपूर्ण एवं खास

पुलिस कॉन्स्टेबल व होम गार्ड पर हमला, दो गिरफ्तार

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल और होमगार्ड पर हमला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में सोमवार सुबह एक कॉन्स्टेबल और होमगार्ड पर हमला किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहम्मद अली (32) और मोहम्मद सुल्तान अली (29) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि द्वारका सेक्टर 23 के पुलिस थाने में तैनात कॉन्स्टेबल राजीव और होमगार्ड अजय कुमार सुबह करीब चार बजे इलाके में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कबाड़ की एक दुकान के अंदर उन्होंने तीन-चार संदिग्ध लोगों को देखा. दोनों ने संदिग्धों से पूछताछ करने की कोशिश की।

एम.वी.राव झारखंड के नए डीजीपी, चौबे दिल्ली स्थानांतरित

रांची (आरएनएस)। झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दो आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिसके अनुसार एम.वी.राव को प्रदेश का नया डीजीपी एवं वर्तमान डीजीपी कमलनयन चौबे का विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण कैम्प नई दिल्ली स्थानांतरण किया गया है।

कोरोना से महाराष्ट्र में बुजुर्ग की मौत

» देश में मरने वालों की संख्या 3 हुई

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीन से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस का असर अब भारत में दिखने लगा है. महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते एक 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है. वहीं इस शख्स की पत्नी भी कोविड 19 से संक्रमित पाई गई है. महाराष्ट्र में हुई इस मौत के बाद भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़कर 127 पर पहुंच गई है. कस्तूरबा अस्पताल में हुई बुजुर्ग की इस मौत के बाद राज्य प्रशासन भी हरकत में आ गया है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शहयाद्री गेस्ट हाउस में आपात बैठक बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को महाराष्ट्र में 5 नए मामले सामने आए है. ये सभी नागरिक विदेशी हैं।

अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया से भारत आने वाले यात्री प्रतिबंधित

नईदिल्ली (आरएनएस)। विगत 11 मार्च और 16 मार्च 2020 को जारी किए गए यात्रा परामर्श को जारी रखते हुए, निम्नलिखित अतिरिक्त परामर्श जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान, फिलीपींस, मलेशिया से भारत आने वाले यात्रियों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की गई है। भारतीय समयानुसार शाम तीन बजे के बाद इन देशों से भारत के लिए कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी। यह निर्देश एक अस्थायी उपाय है और 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी।

जम्मू कश्मीर में 450 लोगों को जेलों में रखा गया: केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर में इस समय लगभग 450 लोगों को विभिन्न जेलों में रखा गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में ए गणेशमूर्ति के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सदन में उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से मिली सूचना के हवाले से बताया कि शांति और अमन-चौन भंग करने वाले अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने तथा लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पत्थरबाजों, शरारती तत्वों, सक्रिय अलगाववादियों आदि सहित लगभग 450 लोगों को इस समय एहतियातन हिरासत में लिया है।

» भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोल मोदी » कोरोना से निपटने में चिकित्सकों व मीडिया के योगदान को सराहा

तीन अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में डाक्टरों और नर्सो सहित चिकित्सा कर्मियों की भूमिका तथा जागरुकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सभी से सतर्क रहने को कहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात भाजपा संसदीय दल की बैठक में कही। बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बजट सत्र की अवधि कम नहीं की जाएगी और यह पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तीन अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत एवं योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं सकारात्मक योगदान के लिये मीडिया की काफी प्रशंसा की।

वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के संदर्भ में किये गए कार्यो को सामने लाने से डाक्टरों, नर्सो, नगरपालिका कर्मियों, हवाई अड्डा कर्मियों, सीआईएसएफ एवं अग्रिम मोर्चे पर जुटे लोगों का मनोबल बढ़ता है। रूडी के अनुसार मोदी ने कहा कि ऐसे में हमें कोविड-19 से मुकाबला

करने के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले विभिन्न लोगों का भी अभिनंदन करना चाहिए। मोदी ने कहा कि सभी स्तर पर विभिन्न प्राधिकार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चत हो कि कोविड-19 नहीं फैले। रूडी के कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि शनिवार एवं रविवार को जब वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से बताया कि मीडिया ने काफी सकारात्मक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है।

विपक्ष ने फिर उठाई संसद सत्र स्थगित करने की मांग

देश में महामारी कोरोना वायरस का देश और दुनिया में खौफ बना हुआ है। इस जानलेवा बीमारी ने लोगों को अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है. भारत में अब तक 126 मामले सामने आ चुके हैं। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एहतियात के तौर पर कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाहॉल, मॉल को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। दफ्तरों में भी लोगों को घर से काम करने पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण मानों देश थम सा गया है, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इतने कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर संसद सत्र को स्थगित क्यों नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को ये मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर हिदायत दी है। कोरोना को लेकर स्कूल, कॉलेज बंद हैं. कोर्ट काफी हद तक बंद हैं। इसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन संसद क्यों अपवाद है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संसद में कुल डेढ़ या दो हजार लोग आते हैं. इसका क्या. संसद को बंद नहीं किया जाए. मैं कुछ दिन बैठने की बात कर रहा हूं. अभी के लिए सत्र को स्थगित कर दिया जाए. हम बाद में भी बैठ सकते हैं।

आर्थिक तबाही के बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही: राहुल

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि देश में आर्थिक तबाही आ रही है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही स्थिति रहती है तो अगले छह महीनों में देश के लोगों को 'अकल्पनीय पीड़ा' का सामना पड़ेगा। गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक तबाही आ आ रही है। यह सुनामी की तरह है। भारत को न सिर्फ कोरोना वायरस, बल्कि आ रही आर्थिक तबाही को लेकर तैयारी रखनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह बार-बार आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर यही स्थित रही तो लोगों को अगले छह महीनों में अकल्पनीय पीड़ा से गुजरना पड़ेगा।

आज फांसी रुकवाने पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे दोषी

» निर्भया गैंगरेप काण्ड

नईदिल्ली (आरएनएस)। निर्भया गैंगरेप के दोषियों में से हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिकाएं लंबित होने को आधार बनाकर फांसी का आदेश स्थगित करवाने के लिए आज फिर पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे। पटियाला हाऊस कोर्ट में आवेदन में आरोप लगाया गया है कि तिहाड़ अधिकारियों को पवन और अक्षय को दोषी ठहराने के लिए क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जारी करना बाकी है। इससे पहले भी पटियाला हाउस कोर्ट कानूनी विकल्पों के आधार पर तीन अलग-अलग डेथ वारंट स्थगित कर दिया है।

एजीआर पर भुगतान के लिए डीओटी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 20 साल की मोहलत

नई दिल्ली (आरएनएस)। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एजीआर के मामले में दूरसंचार कंपनियों को राहत देने का मन बना लिया है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए के भुगतान के लिए 20 साल समय की मंजूरी देने की मांग की।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया। दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए के भुगतान के लिए 20 साल समय की मंजूरी देने की मांग की। दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों के प्रतिकूल कामकाज का अर्थव्यवस्था और देशभर के उपभोक्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग द्वारा शीर्ष कोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया कि कोर्ट के फैसले (अक्टूबर 2019) से प्रभावित सभी लाइसेंसधारकों को बाकी के भुगतान के लिए 20 साल के वार्षिक किस्तों में भुगतान की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बारे में डीओटी ने कहा है कि फैसले की तारीख के बाद मूलधन व जुर्माना पर ब्याज नहीं लगेगा, जबकि बकाए पर 8 फीसदी के ब्याज से सरकार को भुगतान किया जाना चाहिए।

फ्लोर टेस्ट की याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टली

» पक्षकारों, मुख्यमंत्री और स्पीकर को नोटिस जारी

नईदिल्ली (आरएनएस)। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी को अभी और इंतजार करना होगा। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। ऐसा कांग्रेस सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि के न पहुंचने की वजह से हुआ।

अब मामले पर बुधवार को 10.30 बजे सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि वे दूसरे

पक्ष की भी बात सुनना चाहते हैं। अब कोर्ट ने सभी पक्षकारों, मुख्यमंत्री और स्पीकर को भी नोटिस जारी किया है। सबको कल अपना पक्ष रखना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर सोमवार को भोपाल में सुबह से रात तक काफी गहमागहमी रही। सुबह विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल के भाषण से हुई, राज्यपाल ने एक मिनट में भाषण दिया और चल दिए। इसके बाद स्पीकर ने 26 मार्च तक कोरोना के नाम पर विधानसभा स्थगित कर दी। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही सभी 106 बीजेपी विधायकों की राजभवन में परेड कराई। शाम होते-होते राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने को कहा और रात होते-होते कमलनाथ राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग हुई थी। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। बीजेपी ने उम्मीद जताई थी कि कर्नाटक की कहानी मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी।

भारतीय नौसेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमिशन

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के स्थाई कमिशन मामले पर फैसला सुना दिया है। आदेश के मुताबिक नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमिशन दिया जाएगा।

» सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं और पुरुष अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब महिलाएं कई तरह के लाभ पाने की हकदार होंगीं। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

रक्षा राज्यमंत्री ने दिया था ये बयान

रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी गंभीरता से मानेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि महिलाओं को पुरुषों की ही तरह कमांड पोस्ट पर भी तैनात करना चाहिए। सरकार ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा में 14 साल पूरे करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। रक्षा मंत्रालय ने इसके खिलाफसुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

अदालत ने आर्मी के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। दरअल 1950 में बने आर्मी ऐक्ट के तहत महिलाओं को परमानेंट कमिशन के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। इसके 42 साल बाद यानी 1992 में सरकार ने पांच ब्रांच में महिला अधिकारी बनाने की अधिसूचना जारी की। 17 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमिशन दिया जाए।

पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा

नईदिल्ली (आरएनएस)। हिन्दी के राजभाषा से जुड़े पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। द्रविड़ मुनेत्र कषगम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दिये जाने पर अपनी-अपनी सीटों के पास खड़े होकर हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन किया। द्रमुक सदस्यों ने कहा कि हिन्दी को पूरे देश में थोपा नहीं जा सकता, इसलिए इससे संबंधित पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह तमिलनाडु की जनता की हृदय की आवाज है इसलिए उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि देश के ज्यादातर हिस्सों में हिन्दी भाषा बोली जाती है लेकिन राज्यों की मातृभाषा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। किसी भी राज्य पर जबरन हिन्दी नहीं थोपी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि जिन राज्यों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है वहां भी हिन्दी का काफी प्रयोग किया जा रहा है।

राज्यसभा में छाया वर्मा ने की रसोई गैस की कीमतों को वापस करने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस की एक सदस्य ने रसोई गैस की कीमतों में की गयी वृद्धि पर चिंता जताते हुए सरकार से इसे वापस लिए जाने की मांग की। कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने उज्ज्वला योजना का काफी प्रचार किया था लेकिन रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण सिलेंडर फिर से भरा पाना कठिन हो गया है।

वर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में कमी आने के बावजूद सरकार समय समय पर रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर रही है। उन्होंने राशन कार्ड के जरिए मिलने वाले केरोसिन के अब बंद हो जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में गरीब लोग खाना कैसे बनाएंगे।

शून्यकाल में ही सपा सदस्य जया बच्चन ने केंद्रीय विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों के बेहतरीन प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षकों की पेंशन कम हो जाती है। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों को उनका सम्मान दिया जाना चाहिए। केसी-एम के सदस्य जोस के मणि ने कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की आशंका जतायी और सरकार से मांग की कि 10 लाख रूपये तक के कर्ज पर ब्याज माफकर दिया जाना चाहिए। तेदेपा के के रवींद्र कुमार ने अमरावती और विशाखापत्तम की मेट्रो परियोजनाओं से जुड़ा मुद्दा उठाया।

ओलंपिक तैयारी को छोड़कर बाकी सारे राष्ट्रीय खेल शिविर स्थगित

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोविड 19 महामारी के कारण सभी राष्ट्रीय शिविर आगामी आदेश तक स्थगित कर दिये गए हैं हालांकि तोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे।

खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों पर अकादमीय प्रशिक्षण भी निर्लंबित रहेगा। ओलंपिक इस साल जुलाई अगस्त में होने हैं। रीजीजू ने कहा कि कोविड 19 के चलते साइ ने तय किया है कि सभी राष्ट्रीय शिविर स्थगित रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और एसटीसी भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। रीजीजू ने कहा कि यह कदम अस्थायी और एहतियाती है और हालात सुधरने पर प्रशिक्षण बहाल कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी और एहतियातन उठाया गया कदम है। मैं सभी युवा खिलाड़ियों से अपील करता हूं कि दिल छोटा नहीं करें। हम हालात की समीक्षा करके जल्दी ही अकादमीय प्रशिक्षण फिर शुरू करेंगे। भारत में अभी तक निशानेबाजी विश्व कप और इंडिया ओपन गोल्फ स्थगित किया गया है। वहीं बैडमिंटन का इंडिया ओपन भी रद्द कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही सरकार ने खिलाड़ियों

के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं के संबंध में दो परामर्श जारी किये थे। मंत्रालय ने कहा था कि तोक्यो ओलंपिक क्वालीफायर के लिये विदेश में खेल रहे खिलाड़ी अपना अभ्यास जारी रखेंगे। रीजीजू ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय टूर्नामेंटों पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन वे बिना दर्शकों के होंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ इंडियन ग्रां प्री का आयोजन कर रहा है जो ओलंपिक क्वालीफायर भी है। यह 20 मार्च से शुरू होगा और दर्शकों के बिना खेला जायेगा। बीसीसीआई, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ समेत राष्ट्रीय खेल महासंघों ने घर से काम करने का फैसला लिया है।